उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्न औद्योगिक उपक्रमों एवं वित्तीय पुर्निर्माण बोर्ड में पंजीकृत किया जाता है, ताकि उनके नवीकरण/पुनर्स्थापन के सम्बन्ध में पैकेज तैयार किए जा सकें । घाटा उठाने वाले अन्य उपक्रमों के सम्बन्ध में प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धन एवं कामगारों के परामर्श से समयबद्ध नवीकारण रणनीति विकसित की जाती है/अपनायी जाती है । इस प्रकार की रणनीतियों में अन्य बातोम के साथ-साथ निदेशक मण्डल का व्यावसायीकरण, निधियां प्रदान करना संगठनात्मक एवं पूंजीगत पूनर्गठन आदि शामिल है ।

(ग) वर्तमानत : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) और (ड़) जी, नहीं । केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मण्डाळॉ में व्यावसायिकों/ विशेषज्ञों को शामिल करके उनका व्यावसायीकरण किया जाता है । इसके साथ ही, सरकारी उघम चयन मण्डल सरकारी उपक्रमों में निदेशम-मण्डल स्तरीय पदों, यथा मुख्य कार्यपालकों तथा कार्यकारी निदेशकोम के लिए भर्ती करता है तथा उन्हें उत्पादन, विपणन, वित्त, कार्मिक आदि प्रभागों के प्रमुख का भार सौंपा जाता है ।

Closure of small and medium SSIs

478. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether in a very short span 6,00,000 small and medium scale industrial units have been closed down in the country, as reported in the Hindustan Times dated the 6th May, 1998;

(b) whether more than 83 per cent of die work force does not even come under the purview of the existing laws;

(c) if so, the reasons therefor and in what manner Government propose to tackle the industrial strife; and

(d) whether Government propose to restructure antiquated laws and being forward central legislation for building good industrial relation?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Industrial sickness in Bihar

479. SHRI JANARDAN YADAV: Will the
Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have conducted any survey during the last one year in Bihar to find out the number of small, medium and big industrial unit which are lying closed in the State;

(b) if so, the details thereof;

(c) the type of industries like textiles, engineering goods, etc, that, have generally faced closure in the State with details thereof; and

(d) the steps being taken by Central Government for the revival of these closed industries in the State within a time frame?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the Hosue.

मैसर्स सांभर साल्ट लिमिटेड का हस्तान्तरण

480. **श्री ओंकार सिंह लखावत :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में मैसर्स सांभर साल्ट लिमिटेड नामक भारत सरकार का उपक्रम कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) क्या उपक्रम लाभ में चल रहा है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राजस्थान सरकार ने नमक उद्योग को घाटे से निकालने एवं हजारों बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सांभर झील क्षेत्र को राज्य सरकार को लौटाने हेतु अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(च) क्या सरकार ने पहले भी 1960 में डीडवाना नमक इकाई, जो उस समय घाटे में चल रही थी, को राजस्थान सरकार को हस्तान्तरित कर दिया था?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) जी, हां । मैसर्स सांभर साल्ट लिमिटेड 30 सितम्बर, 1964 से राजस्थान में कार्य कर रहा है ।

(ग) जी, हां। मैसर्स सांभर साल्ट लिमिटेड द्वारा पिछले तीन वर्षो के दौरान अर्जित किया गया लाभ निम्नानुसार है:-

(लाख रुपए में)

1995-96	45.81
1996-97	17.32
1997-98	14.50

(घ) और (ड़) राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से सांभर साल्ट लिमिटेड को राजस्थान सरकार को हस्तान्नरित करने का अनुरोध किया था। अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया, चूंकि, यह महसूस किया गया था कि हस्तान्तरन कंपनी के संपूर्ण हित में नहीं होगा।

(च)जी, हां।

Recommendations of Abid Hussain Committee in SSIs

481. SHRI J. CHITHARANJAN:
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

Will the Minister of INDUSTRY bo pleased to state:

(a) the main recommendations of the Abid Hussain Committee on small scale sector industries; and

(b) the Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) and (b) A statement is placed on the Table of the House, giving main recommendations of the Abid Hussain Committee and Government's reaction thereon.

Statement

Expert Committee on Small Enterprise

(Abid Hussain Committee)

Main Recommendations/Government's Reaction

RECOMMENDATION	GOVERNMENTS REACTION
1. A separate law should be enacted for enterprises. The bjective of the law be to define the small enterprise sector outline the broad frame work for the promotion of the sector.	The Government has no objection. requires wide consultation with all viz. State Governments, Associations, clearly identify the areas which require legislation.
2. The Limited Partnership Act should enacted as soon as possible.	The recommendation is accepted.
3. Urgent action be taken to amend or laws that we barrier to the progress and threshold level for the application of labour laws should be to the units having SO/100 workers without power.	The existing provisions of labour and related Laws would be listed out and in detail.
4. The concept of small sector be include small Scale business and enterprises.	In view of the inadequacy of the credit, widening of the sector is not desirable. business and service related small scale enterprise having an investment upto increased limit for tiny unit (Rs. 25 be included within the small sector, as done up to Rs. 5 lakhs of investment at
5. The investment limit for SSE be to Rs. 3 crores and for tiny units to lakhs.	Agreed and action already taken, investment limit is now under review.